

प्रेषक,

मनोज चन्द्रन,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण, उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी, नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक: 10 अगस्त, 2016

विषय: जनपद देहरादून, हरिद्वार एवं उधमसिंह नगर में पूर्ण कालिक (Full Time) किशोर न्याय बोर्ड गठन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल के पत्र सं0-3272/UHC/XVII/5/Admin-B/2003 दिनांक 11 जुलाई, 2016 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के सफल क्रियान्वयन हेतु जनपद देहरादून, हरिद्वार एवं उधमसिंह नगर में पूर्णकालिक (Full Time) किशोर न्याय बोर्ड के संचालन हेतु शासनादेश सं0-838/XVII-2/16-13(म0क0)/2015 दिनांक 14 जून, 2016 को निरस्त करते हुए शासनादेश सं0-1706/XVII-2/14-01(42)/2009 दिनांक 17 दिसम्बर, 2014 में स्वीकृत निम्नलिखित अस्थायी पदों को दिनांक 01.03.2015 से पूर्ववर्ती प्रभाव से दिनांक 28.02.2017 तक यदि ये पद बिना पूर्व सूचना के पहले ही समाप्त न कर दिये जाए, निरन्तरता प्रदान की जाती है :-

क्र0 सं0	पद नाम	वेतनमान (अपुनरीक्षित वेतनमान)	पुनरीक्षित वेतनमान		एक न्यायालय हेतु पदों की संख्या	03 न्यायालयों हेतु कुल पदों की संख्या
			पे बैंड में वेतनमान	ग्रेड वेतन		
1.	प्रधान मजिस्ट्रेट/ न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी)	9000-250-10750 -300-13250-350 -14550	27700-770-33090- 920-40450-1080- 44770		1	3
2.	मुन्सरिम	4000-6000	5200-20200	2400	1	3
3.	आशुलिपिक	4000-6000	5200-20200	2400	1	3
4.	रीडर	4000-6000	5200-20200	2400	1	3
5.	शूट क्लर्क एवं मिस. क्लर्क	4000-6000	5200-20200	2400	2	6
6.	चपरासी	4440-7440 ग्रेड पे-1800 (आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरे जायेंगे)			1	3
कुल पद 21						

- 2- उक्त पर होने वाला व्यय सम्बन्धित वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान सं०-15 के "आयोजनेत्तर पक्ष" के लेखाशीर्षक 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 02-समाज कल्याण 102-बाल कल्याण 05-बाल कल्याण कोर्ट बोर्ड की स्थापना के नामे डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-909/XVII(1)/2015 दिनांक 08 अगस्त, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मनोज चन्द्रन)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्या: 973(1)/XVII-2/16-13(म0क0)/2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, ओबेराय मोटर बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
- 2- महानिबन्धक, मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल को पत्र सं०-3272/UHC/XVII/5/Admin-B/2003 दिनांक 11 जुलाई, 2016 के क्रम में।
- 3- प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- निदेशक, समाज कल्याण, निदेशक, समाज कल्याण/सदस्य सचिव, राज्य बाल संरक्षण समिति, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी, नैनीताल।
- 5- अवर सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 6- जनपद न्यायाधीश, देहरादून/हरिद्वार/उधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड।
- 7- जिलाधिकारी, देहरादून/हरिद्वार/उधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड।
- 8- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/हरिद्वार/उधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड।
- 9- निदेशक, एन०आईसी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दिनेश चन्द्र जोशी)

(दिनेश चन्द्र जोशी)
अनु सचिव।